इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40 रुपए

(आईएसओ 9000-2015 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

Committed to professional excellence

खंड संख्या 15 | अंक संख्या 09 | अप्रैल, 2023 | पृष्ठों की संख्या - 9

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ 2
विनियामक के कथन 3
आर्थिक संवेष्ठन 4
नयी नियुक्तियाँ 5
विदेशी मुद्रा 5
शब्दावली 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी 6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां 6
संस्थान समाचार.....7
नयी पहलकदमी 8
बाजार की खबरें.....8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति की मुख्य बातें 3 से 6 अप्रैल, 2023

मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 3, 5 और 6 अप्रैल, 2023 को आयोजित बैठक की मुख्य बातें इसके नीचे यथा-वर्णित हैं :

चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के अधीन पुनर्खरीद (repo) दर 6.50% पर अपरिवर्तित।

- स्थाई जमा सुविधा (SDF) दर 6.25% पर अपरिवर्तित।
- सीमांत स्थाई सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 6.75% पर।
- वित्त वर्ष 24 के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि एवं मुद्रास्फीति दर क्रमश: 6.5% तथा 5.2%।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि वृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुये मुद्रास्फीति क्रमिक रूप से लक्ष्य के साथ संरेखित रहे निभाव (accommodation) सुविधा की वापसी पर ध्यान केन्द्रित रखना।
- एकाधिक बैंकों में अदावीकृत (unclaimed) जमाराशियों का पता लगाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल विकसित करना।
- एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) के पदचिन्हों को व्यापक एवं विस्तृत बनाने के लिए बैंकों में पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्थाओं (credit lines) की अनुमति देना।
- भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट (IFSC) बैंकिंग इकाइयों (IBUs) वाले बैंकों को अपतटीय बाजार में निवासी प्रयोक्ताओं को भारतीय रुपए से संबन्धित सुपुर्दगी-योग्य नहीं विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी (derivative) संविदाओं (NDDCs) की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी।

वर्ष 2023 की वित्तीय लेनदेन योजना (FTP) में रुपया व्यापार, ई-काम निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित

प्रोत्साहन-आधारित प्रणाली के स्थान पर उपशमन/माफी एवं पात्रता-आधारित प्रणाली अपनाते हुये वर्ष 2030 तक भारत के निर्यात को बढाकर 2 ट्रिलियन अमरीकी डालर करने का लक्ष्य रख कर सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों (takeaways) के साथ विदेश व्यापार नीति 2023 जारी कर दी है :

- नीति की निरंतरता एवं एक अनुक्रियात्मक ढांचे की व्यवस्था।
- निर्यात मालों/सामानों पर शुल्कों, करों और सरकारी उगाहियों की माफी की योजनाएँ।
- आवेदनों का डिजिटीकरण।
- भारतीय रुपए में व्यापार को संवर्धन।
- स्वत: प्रणाली-आधारित अनुमोदन से विदेश व्यापार से संबन्धित आवेदनों को लाभ।
- विक्रय (merchanting) व्यापार के प्रावधान/की व्यवस्था।
- ई-कामर्स निर्यातों को विदेश व्यापार नीति का लाभ।
- स्कामेट (SCOMET) नीति के तहत दोहरे उपयोग वाली मदों के निर्यात को युक्तिसंगत बनाना।
- राज्यों और जिलों का समावेश करके 'निर्यात हब के रूप में जिले' वाली पहलकदमी पर सक्रिय कार्य।
- एक सतत नीति, उचित आवश्यकतायें होने पर विदेश व्यापार नीति को आंतरायिक रूप से अद्यतन किया जाएगा।

जी20 की ढांचा/रूपरेखा कार्य दल (FWG) की चेन्ने बैठक में ध्यान का केंद्र वैश्विक मुद्रास्फीति, उभरते बाजार

जोखिमों को नियंत्रित करना

हाल ही में भारत की अध्यक्षता में चेन्नै में जी20 के ढांचा/रूपरेखा कार्य दल की दूसरी बैठक सम्पन्न हुई। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री वी॰ अनंत नागेश्वरन और यू॰ के॰ ट्रेजरी के मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री क्लेयर लोम्बार्डेल्ली की सह-अध्यक्षता में आयोजित उक्त द्विदिवसीय बैठक में विचार-विमर्श में वैश्विक आर्थिक प्रत्याशा एवं जोखिमों का समावेश था। बैठक में वैश्विक मुद्रास्फीति तथा उभरते वित्तीय जोखिमों पर नियंत्रण पर बल दिया गया।

इस बैठक में वैश्विक स्थूल आर्थिक मुद्दों और सुदृढ़, वहनीय, संतुलित एवं समावेशी वृद्धि के लिए नीतिगत सहयोग (SSBIG) पर विचार विनिमय किया गया। विश्व बैंक समूह (WBG), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए नेटवर्क (NGFS) तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने वैश्विक मुद्रास्फीति, खाद्य तथा ऊर्जा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन एवं संक्रमण नीतियों के स्थूल आर्थिक निहितार्थों जैसे मुद्दों पर विस्तृत तकनीकी प्रस्तुतीकरण पेश किए।

भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय/सेंट्रल बोर्ड ने वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक स्थिति, चुनौतियों की समीक्षा की

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय/सेंट्रल निदेशक मण्डल की 601वीं बैठक गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास की अध्यक्षता में हैदराबाद में आयोजित हुई थी। आक्रामक मौद्रिक कठोरता के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के बैंकों के समाप्त (belly-up) होने की पृष्ठभूमि में बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति की समीक्षा की तथा वर्तमान भौगोलिक-राजनीतिक घटनाओं सहित इससे जुड़ी चुनौतियों का अध्ययन किया। नीति-निर्धारकों का कहना है कि वैश्विक विक्षोभ के बावजूद भारतीय बैंकिंग प्रणाली अच्छी स्थिति में बनी हुई है।

सरकार ने अनिवासी फर्मों को रायल्टियों पर रोक रखे गए कर बढ़ाकर 20% किए

वित्त विधेयक, 2023 में विहित संशोधन करते हुये सरकार ने अनिवासी कंपनियों द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए अर्जित की जाने वाली रायल्टियों और शुल्कों पर रोक रखे गए (withholding) कर की दर 10% से बढ़ाकर 20% करते हुये दोगुनी कर दी है।

कराधान करारों में दोहरा कराधान परिहार शामिल होने पर कंपनियाँ 10 से 15% की लाभकारी कर दर प्राप्त कर सकती हैं। हालांकि, विदेशी फर्म से कर निवास/रेजिडेंसी प्रमाणपत्र और संबन्धित प्रलेखन की आवश्यकता तब भी बनी रहेगी।

विनियामक के कथन

यूपीआई और रूपे जैसे हमारे भुगतान उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीयकृत करें : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास

भुगतान प्रणाली प्रचालक सम्मेलन (PSO) का उदघाटन करते समय एक व्याख्यान देते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने संबन्धित कंपनियों को भारत की ई-भुगतान गाथा को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जी20 की अध्यक्षता का एक प्लेटफार्म के रूप में उपयोग करने तथा एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) एवं रूपे जैसे भुगतान उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीयकृत करने हेतु अवसर का उपयोग करने हेतु प्रबोधित किया।

इस बात पर बल देते हुये कि शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान विजन 2025 के तहत 'प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सर्वत्र, सर्वदा ई-भुगतान (4 ई) उपलब्ध कराने' के प्रति प्रतिबद्ध है, उन्होंने यह कहा कि एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ और रूपे नेटवर्कों के विस्तारशील वैश्विक पदचिन्ह से सीमा-पार वाले भुगतान हर हाल में अपेक्षाकृत आसान हो जाएंगे।

हालांकि, गवर्नर ने इस बात का भी स्मरण कराया कि संभाव्य कमियों (downsides) के साथ भुगतान एवं निपटान गंभीर व्यवसाय हैं, इस प्रकार की कमियों को न्यूनीकृत करने तथा खूबियों (upsides) से लाभ उठाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर है, बैंकिंग प्रणाली आघात-सह है: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास

17वें के॰ पी॰ होरमिस स्मारक समारोह में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने संयुक्त राज्य अमेरिका में तीन बैंकों के विफल हो जाने की पृष्ठभूमि में बैंकों के लिए विवेकशील आस्ति देयता प्रबंधन, सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन तथा देयताओं एवं आस्तियों

में वहनीय वृद्धि सुनिश्चित करने की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने आवधिक दबाव परीक्षण किए जाने और पूंजी का सुरक्षित भंडार निर्मित किए जाने पर भी बल दिया।

गवर्नर ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक ऐसे आंकड़े /डेटा का उल्लेख किया जिसमें अल्प आय वाले 15% देशों के ऋण विपत्ति में होने का अनुमान लगाया गया था। अल्प आय वाले 45% अतिरिक्त देश तथा उभरते बाजार वाली 25% अर्थव्यवस्थायें भी ऋण विपत्ति के उच्च जोखिम से गुजर रही थीं। उभरते बाज़ारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थितियों की निरंतर कठोरता के परिणामस्वरूप पूंजी बहिर्वाह हुआ जिसके फलस्वरूप आरक्षित निधि का क्षय हुआ, मुद्रा में तीव्र अवमूल्यन हुआ तथा चढ़ती आयातित मुद्रास्फीति के दबावों का सामना करना पड़ा। तथापि, भारत के विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढने वाली एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था हो जाने की आशा है।

रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक स्वागतयोग्य कदम, बेहतर अस्थिरता प्रबंधन आवश्यक: भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर

कैरो में आयोजित 17वें भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI) के सम्मेलन में मुख्य व्याख्यान देते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम॰ राजेश्वर राव ने कहा है कि भारत रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण और पूंजीगत खाते की अपेक्षाकृत मुक्त परिवर्तनीयता के मार्ग पर जैसे-जैसे आगे बढ़ता है उसके लिए विनिमय दर की अस्थिरता को नियंत्रित करने हेतु तैयार रहना आवश्यक होगा। जहां रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के स्वयं अपने लाभ हैं, वहीं सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को उसके साथ आने वाली चुनौतियों एवं जोखिमों से निपटना होगा।

आर्थिक वृद्धि से विदेशी मुद्रा बाज़ारों में सहभागिता का दायरा बढ़ जाता है। भारतीय बैंकों को रुपया व्युत्पन्नियों (derivatives) के लिए अपतटीय सुपुर्दगी योग्य नहीं बाजार में सहभागिता करने की अनुमति दिये जाने के परिणामस्वरूप नए सहभागियों के साथ एक पूर्णत: नया बाजार खुल गया है। पिछले कुछेक दशकों में भारत के विदेशी मुद्रा बाजार के प्रचुर विकास एवं नवोन्मेष की प्रक्रिया से गुजरने के फलस्वरूप शीर्ष बैंक बदलते वैश्विक और घरेलू स्थूल-वित्तीय वातावरण के अनुरूप एक स्थिर गति से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

कदाचरण पर निगरानी रखने, उपभोक्ताओं को संरक्षित करने हेतु फिंटेक कंपनियों के लिए स्व-विनियामक संगठन माडेल अच्छा

अहमदाबाद में आयोजित फिंटेक कंपनियों पर अंतराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम॰ के॰ जैन ने यह मत व्यक्त किया है कि संस्थाओं/कंपनियों के कदाचार पर निगरानी रखने, उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षित करने तथा उच्च अभिशासन मानकों को बनाए रखने के लिए भारतीय फिंटेक कंपनियों को अपने आप को एक स्व-विनियामक संगठन (SRO) माडेल के अधीन संगठित करना चाहिए। उक्त स्व-विनियामक संगठन क्षेत्र/सेक्टर एवं विनियामकों के बीच एक दुतरफा सेतु भी बन सकता है। फिंटेक कंपनियों को सुदृढ़ ग्राहक केन्द्रित उत्पाद इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि ग्राहक साइबर-सुरक्षा के उल्लंघनों, तकनीकी खामियों (glitches) तथा धोखाधड़ियों से पैदा होने वाली कंपनी प्रेरित हानियों से संरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि ग्राहक की अनुरूपता एवं उपयुक्तता का अनुरक्षण किया जाना चाहिए और अप-बिक्री अथवा अविवेकी उधार को सख्ती से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। आगे यह भी कहते हुये कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)- लेखा समाकलक (Account Aggregator) के संबंध में 2016 के भारतीय रिजर्व बैंक के ढांचे – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी –समकक्ष से समकक्ष को उधार से संबन्धित 2017 के दिशानिर्देश और हाल के डिजिटल उधार संबंधी दिशानिर्देश ये सभी पैदा होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए अभीष्ट अनुकूली विनियमन के उदाहरण हैं।

आर्थिक संवेष्ठन

आर्थिक कार्य विभाग ने फरवरी, 2023 की अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा जारी कर दी है।

इसकी मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- खाद्य और मुख्य मुद्रास्फीति में गिरावट के परिणामस्वरूप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति जनवरी, 2023 के 6.5% से थोडी घटकर फरवरी, 2923 में 6.4% रह गई।

- फरवरी, 2023 में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में रोजगार के मामले में पीएमआई सूचकांक विस्तारवादी क्षेत्र में बने रहे, विनिर्माताओं को में नए काम की आवक में वृद्धि परिलक्षित हुई।
- सितंबर, 2022 के अंत में भारत के कारपोरेट क्षेत्र का ऋण-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात उसकी पारंपरिक प्रवृत्ति से लगभग 12.3 प्रतिशत कम रहा, जिससे यह पता चलता है कि कारपोरेट क्षेत्र के पास उधार लेने के लिए पर्याप्त अवसर हैं।
- सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर ध्यान बढ़ाए जाने के बाद 2011-12 की कीमतों पर सकल नियत पूंजी निर्माण वित्त वर्ष 22 के पहले नौ माह में 34 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 23 की तदनुरूपी अवधि में 39 लाख करोड़ रुपए हो गया।
- वर्ष 2022-23 की अप्रैल-जनवरी अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) तथा आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में वर्षानुवर्ष सकारात्मक वृद्धि परिलक्षित हुई, जिससे उत्पादन परिमाण में वृद्धि का संकेत प्राप्त होता है।
- वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में तिजारती निर्यात में अल्प वृद्धि परिलक्षित हुई अप्रैल-फरवरी 2022-23 की अवधि में वे वर्षानुवर्ष 7.6% की दर से बढ़ते हुये आघात-सह बने रहे।

विश्व बैंक द्वारा जारी भारत के आर्थिक विकास के प्रमुख मुद्दे

- सुदृढ़ निवेश गतिविधि तथा उल्लसित निजी उपभोग के कारण समग्र वृद्धि सुदृढ़ बनी रही।
- अपेक्षाकृत धीमी उपभोग वृद्धि एवं चुनौतीपूर्ण बाह्य/विदेशी स्थितियों के कारण वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विश्व बैंक ने सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को संशोधित करके उसे 6.6% के स्थान पर 6.3% कर दिया है।
- आस्ति की गुणवत्ता में सुधार एवं निजी क्षेत्र की सुदृढ़ ऋण वृद्धि के कारण भारत का वित्तीय क्षेत्र सुदृढ़ बना रहा।
- सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में ऋण का अनुपात स्थिर रहने का अनुमान है तथा चालू खाते के घाटे में कमी आने का अनुमान है।
- अमेरिका और यूरोप में वित्तीय बाजार में हाल की घटनाएँ भारत सहित उभरते बाज़ारों के लिए अल्पावधिक निवेश प्रवाह के प्रति जोखिम उपस्थित कर सकती हैं।
- भारत के बैंक अच्छी तरह पूंजीकृत बने हुये हैं।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री सुमंत कठपलिया	इंडसइंड बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पुनर्नियुक्त

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	24 मार्च, 2023 के दिन करोड रुपए	24 मार्च, 2023 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	4773649	578778
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4204245	509728
1.2 सोना	375117	45480
1.3 विशेष आहरण अधिकार	151923	18419
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	42364	5151

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

अप्रैल, 2023 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	4.83
जीबीपी	4.1767
यूरो	2.894
जापानी येन	-0.015

मुद्रा	दरें
न्यूजीलैंड डालर	4.75
स्वीडिश क्रोन	2.889
सिंगापुर डालर	3.5253
हांगकांग डालर	1.33842

मुद्रा	दरें
कनाडाई डालर	4.5000
आस्ट्रेलियाई डालर	3.60
स्विस फ्रैंक	1.408664

मुद्रा	दरें
म्यामार रुपया	2.72
डैनिश क्रोन	2.5410

स्रोत : www.fbil.org.in

शब्दावली

रोका गया कर

रोके गए कर से आशय है वह धनराशि जो कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी की सकल मज़दूरियों से काट लेता है और उसका सीधे सरकार को भुगतान करता है। नियोक्ता रोक रखे गए करों को कर्मचारी के नाम पर सीधे भारतीय राजस्व सेवा (IRS) को विप्रेषित करता है। रोका गया कर अमरीकी निवासियों और ऐसे अनिवासियों से काटा जाता है जो अमरीकी स्रोतों से धनराशि अर्जित करते हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (ROAA)

औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ किसी फर्म की आस्तियों की लाभप्रदता का निर्धारण करने हेतु प्रयुक्त एक संकेतक होता है तथा इसका उपयोग अधिकांशत: बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय कार्य-निष्पादन को मापने के एक साधन के रूप में किया जाता है। प्रतिलाभ यह दर्शाता है कि कोई कंपनी लाभ सृजित करने के लिए अपनी आस्तियों का कितनी अच्छी तरह उपयोग करती है तथा यह उसी उद्योग में वैसी ही कंपनियों के साथ तुलना करते समय सर्वोत्तम रीति से कार्य करता है। ऐसी कंपनियाँ जो प्रारम्भ में उपकरणों एवं अन्य आस्तियों में अत्यधिक निवेश करती हैं, उनका औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ विशिष्ट रूप से कमतर होता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अप्रैल, 2023 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थल
आंतरिक लेखा-परीक्षकों के लिए कार्यक्रम	5 से 6 अप्रैल, 2023	प्रौद्योगिकी पर आधारित
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्तीयन पर कार्यक्रम	10 से 12 अप्रैल, 2023	वही
निवारक सतर्कता एवं धोखाधड़ी प्रबंधन पर कार्यक्रम	11 से 13 अप्रैल, 2023	वही
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र हेतु प्रशिक्षण	11 से 13 अप्रैल, 2023	वही
मूल ऋण विश्लेषण पर कार्यक्रम	17 से 18 अप्रैल, 2023	वही
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण	18 से 20 अप्रैल, 2023	वही

संस्थान समाचार

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा 38वें सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान का आयोजन

संस्थान ने 6 अप्रैल, 2023 को 38वें सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान का आयोजन प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से किया। इस बार उक्त व्याख्यान इन्टरनेशनल फाइनैन्सियल सर्विसेज सेंटर अथारिटी (IFSCA) के अध्यक्ष श्री इंजेति श्रीनिवास द्वारा ''रोल आफ आईएफएससी इन इंडियाज ग्लोबलाइजेशन'' (Role of IFSC in India's Globalization) विषय पर दिया गया। उदघाटन भाषण पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के उपाध्यक्ष श्री ए॰ के॰ गोयल द्वारा दिया गया। उक्त व्याख्यान को खूब पसंद किया गया तथा उसमें बैंकरों की अच्छी-ख़ासी उपस्थिति रही।

आईआईबीएफ ने बैंकिंग एवं वित्त इयरबुक, 2023 का दूसरा संस्करण जारी किया

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने ''बैंकिंग एवं वित्त इयरबुक, 2023'' का बहु-प्रतीक्षित दूसरा संस्करण जारी कर दिया है। यह 31 दिसंबर, 2022 तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रवृत्तियों, विशेषज्ञों के विचारों तथा बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्षेत्रों (verticals) में हुये विनियामक परिवर्तनों के समावेश वाली एक व्यापक सार-पुस्तिका (digest) है। इसके अतिरिक्त, इसमें पाठक को एक हितकर वाचन अनुभव प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गए महत्वपूर्ण व्याख्यानों के उद्धरण, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के जर्नल बैंक क्वेस्ट में प्रकाशित चुनिन्दा आलेखों को शामिल किया गया है। यह पुस्तक अमैजान पर पेपरबैक रूप मे तथा एक प्रेरक (kindle) संस्करण दोनों ही रूपों में उपलब्ध है। उक्त पुस्तक हमारे प्रकाशक मैसर्स टैक्समैन पब्लिकेशन्स (प्रा॰) लिमिटेड के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर भी उपलब्ध है।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स – अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक पाठ्यक्रम का सयुक्त रूप से आयोजन

संस्थान ने जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के साथ एक करार कर रखा है। उक्त पाठ्यक्रम 4-6 घंटों के शिक्षण के समावेश वाले ई-शिक्षण (E-learning) के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसके बाद एक मूल्यांकन सत्र आयोजित किया जाएगा। प्रमाण पत्र इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए जाएंगे।

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी – संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या उन्हें अधिक समसामयिक, सकल्पनात्मक बनाने तथा महत्तर मूल्य-वर्धन सुनिश्चित करने के लिए पुनरसंरचित एवं संशोधित कर दी गई है। इस संबंध में संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पाठ्यक्रम को संशोधित किए जाने की आवश्यकता पर सदस्यों को एक सदेश भी संबोधित किया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन विषयों, परीक्षा के स्वरूप, उत्तीर्णन की समय-सीमा, उत्तीर्णन मानदंड आदि के बारे में एक विस्तृत सूचना वेबसाइट पर भी डाली गई है। उक्त संक्रमण को अभ्यर्थियों के लिए अधिक अनुकूल बनाने हेतु नयी पाठ्यचर्या में पुरानी पाठ्यचर्या से कुछेक विषयों के लिए श्रेय (credits) दिये जाने की अनुमति दी गई है। संशोधित पाठ्यचर्या के अधीन परीक्षाएँ मई/जून, 2023 और उसके बाद से आयोजित की जाएंगी। संस्थान द्वारा निषेधात्मक (negative) अंक दिये जाने से संबन्धित नियम को आस्थगित कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा ''बैंकिंग प्रौद्योगिकी'' : 2022-23 (आईआईबीएफ एवं आईडीआरबीटी की संयुक्त पहलकदमी) में रिसर्च फ़ेलोशिप हेतु आवेदन आमंत्रित

संस्थान ''बैंकिंग प्रौद्योगिकी'' : 2022-23 (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एवं बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (IDBRT) की संयुक्त पहलकदमी) में रिसर्च फ़ेलोशिप हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। बैंकिंग प्रौद्योगिकी में रिसर्च फ़ेलोशिप का उद्देश्य तकनीकी और आर्थिक रूप से संभाव्य ऐसी प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित करना है जिनमें बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से योगदान करने की संभाव्यता विद्यमान हो। आवेदनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

बैंक क्वेस्ट के अप्रैल - जून, 2023 तिमाही के लिए आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: ''Competence based Human Resource Management in Banks.''

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/ दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2023 से जुलाई, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2022 से जनवरी, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

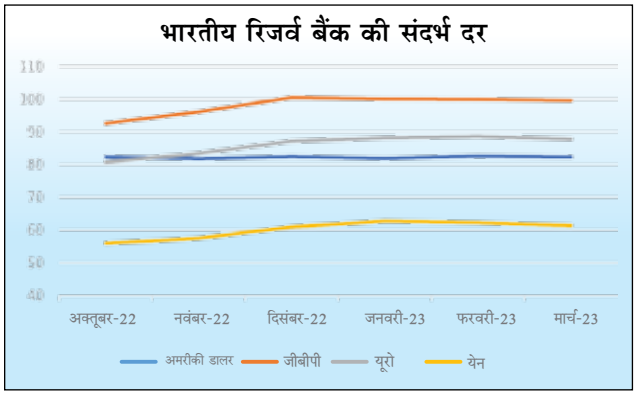

स्रोत: एफबीआईएल

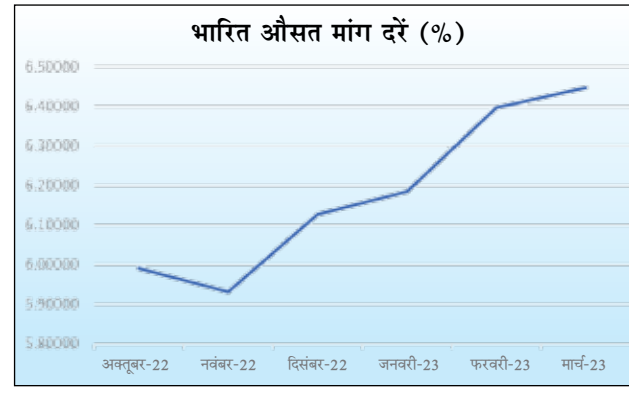

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

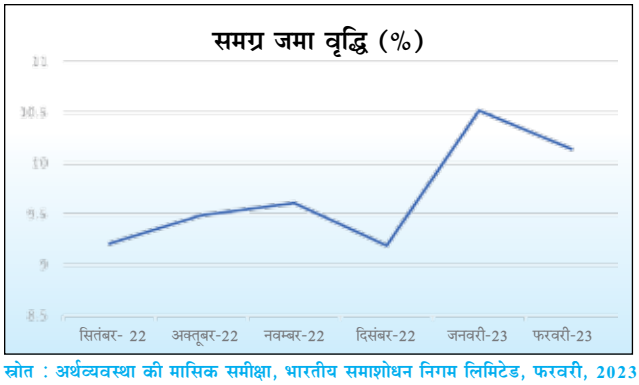

स्रोत : अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, फरवरी, 2023

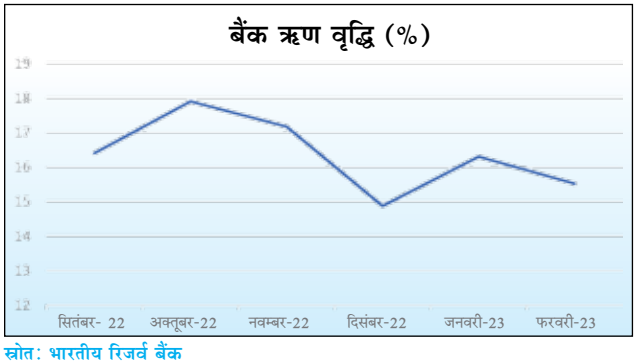

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

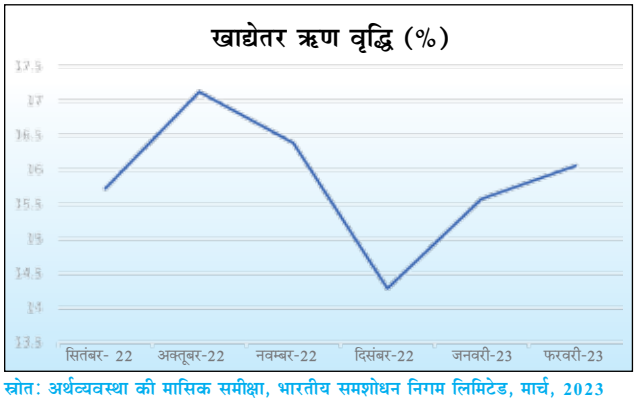

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, मार्च, 2023

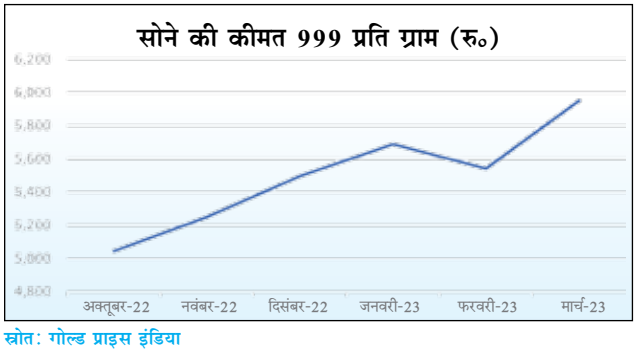

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

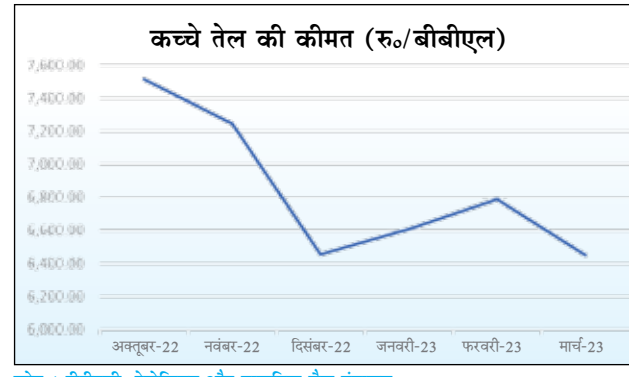

स्रोत : पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

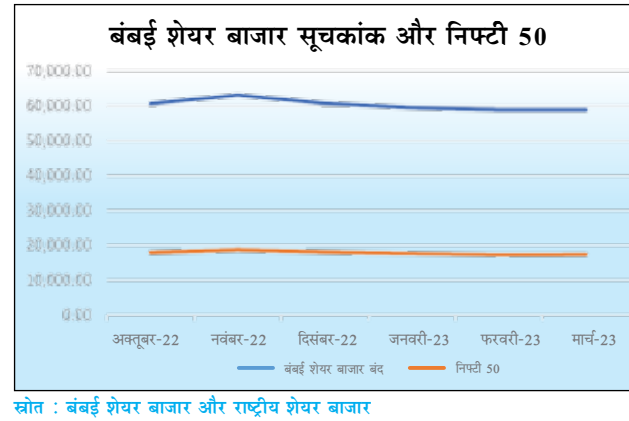

स्रोत : बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in